मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

# मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

सेक्टर-8 ईएसआई अस्पताल डबल ड्राइविंग का शिकार 2
मांगों को लेकर लैब अटेंडेंट ने सीएम सिटी में डाला महापड़ाव 4
गेहूं चावल, दूध, दही,आटा आदि पर जीएसटी के तुगलकी फरमान 5
नौनिहालों की थाली में 'शाकाहारवाद की राजनीति' जायज नहीं 6
शहर को लूटने में ये पांच सरकारी एजेंसियां जुटी हैं 8

वर्ष 36 | अंक 38 | फरीदाबाद | 31 जुलाई 6 अगस्त 2022 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

## विधान सभा कमेटी की नौंटकी

# नगर निगम के अधूरे कामों को लेकर अफसरों को 'धमकाया'

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** शहर में किये जाने वाले जन कार्यों के प्रति सरकार की गंभीरता, जनता को दर्शाने के लिये एक विधानसभा कमेटी बनाई हुई है। गुरूवार को स्थानीय विधायक नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में इसकी बैठक यहां सम्पन्न हुई।

बैठक में निगम के स्थानीय अधिकारियों के अलावा शहरी निकाय प्रशासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता भी मौजूद थे। निगम अधिकारियों द्वारा अपने क्रिया-कलापों के बारे में कमेटी को गलत सूचनायें देने को लेकर विधायक नरेन्द्र गुप्ता ने उन्हें फ़टकारते हुए कहा कि वे झूठ बोल कर सरकार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा।

दरअसल निगम अधिकारी किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं और न ही सरकार कभी बेवकूफ बना करती है। न केवल इस नगर निगम बल्कि राज्य के हर महकमे में कहां क्या हो रहा है इसे जानने के लिये सरकार के पास मीडिया के साथ-साथ पूरा तंत्र मौजूद है जिसके द्वारा वह सब कुछ जानती समझती है। कुल मिला कर जो कुछ भी हो रहा है वह सरकार की जानकारी व मिलीभगत से हो रहा है।

कमेटी नामक नाटक मंडली के सदस्य : नरेन्द्र गुप्ता, सीमा त्रिखा, नीरज शर्मा

कमेटी के चेयरमैन एवं विधायक नरेन्द्र गुप्ता ने जो कड़ी कार्रवाई करने व किसी को भी न बख्शने की धमकी दी है, वह एकदम थोथी है। निगम का इतिहास बताता है कि आज तक यहां किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, किसी के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यदि किसी निगमायुक्त ने किसी लुटेरे कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर भी दी तो मुख्यालय में बैठे उच्चाधिकारी तथा राजनेता उसकी पदोन्नति कर देते हैं।

जिस राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निरीक्षण करने कमेटी गई थी वह तो चेयरमैन नरेन्द्र गुप्ता व सभी विधायकों को रोज ही दिखता है। संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि इस अच्छे भले स्टेडियम को जान बूझकर केवल इसलिये बर्बाद किया गया है कि गुजराती फर्म को इस शहर का डेढ़ सौ करोड़ रुपया लूटने का अवसर दिया जा सके। इसी तरह अन्य तमाम काम जिनका उन्होंने निरीक्षण किया वे भी इन्हें हर रोज मीडिया द्वारा दिखाये जाते हैं। गुप्ता जी दूर क्यों जाते हो, आपके दफ्तर के करीब ही सेक्टर 10 व 11 की विभाजक सड़क का उद्घाटन जो आपने स्वयं किया था, उसकी आज क्या हालत है? गुप्ताजी से पहले इसका नारियल पूर्व मंत्री विपुल गोयल वर्षों पहले फोड़ चुके हैं। इससे भी बद्दतर हालत हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक की है।

**कुल मिलाकर सरकार द्वारा इस तरह की कमेटियों द्वारा ऐसी नौटंकियां करा कर जनता को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि सरकार वास्तव में ही जनता के दुखों का संज्ञान ले रही है।**

# नेशनल पावर ट्रेनिंग इस्टीट्यूट में मंत्री कृष्णपाल ने दागे झूठ के गोले

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने दिनांक 27 जुलाई को (एनपीटीआई) के सभागार में बिजली क्षेत्र के उच्च प्रशिक्षित इंजीनियरों को भाषण देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में जो काम 2030 तक पूरे होने वाले थे उन्हें मोदी जी ने 2021 में ही पूरा करा दिया। वर्ष 2014 में जहां बिजली का कुल उत्पादन 2,48,554 मेगावाट होता था वह अब बढ़कर 4,00,000 मेगावाट हो गया। यह देश की कुल आवश्यकता से 1,85,000 मेगावाट अधिक हो गई है। इसलिये अब भारत पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात भी करने लगा है।

मंत्री महोदय के प्रवचन को सुनकर बिजली क्षेत्र के, ज्ञानवान प्रशिक्षु मंद-मंद मुस्करा रहे थे और आपस में ही फुसफुसा कर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि बीते आठ साल में मोदी जी ने कितने पावर प्लांट खड़े कर दिये, उनका विवरण मंत्री जी क्यों नहीं दे रहे? मंत्री यह भी तो बतायें कि किस देश को कितनी बिजली भेजकर भारत ने कितना पैसा कमाया है?

पिछले दिनों पूरे देश भर ने देखा था कि कोयले के आभाव में अधिकांश बिजली प्लांटों का उत्पादन न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला गया था। कई प्लांट तो बंद भी करने पड़े। वह बात अलग है कि कोयले का यह आभाव मोदी जी ने इसलिये खड़ा किया था ताकि उनके मित्र अडाणी का विदेशी कोयला देशी प्लांटों के मत्थे मढ़ा जा सके। इसके चलते बिजली उत्पादन की लागत बढ़नी निश्चित है जिसे उपभोक्ताओं से ही वसूला जायेगा।

पूरे देश को तो छोड़िये, मंत्री जी के इस अपने शहर में लोग किस प्रकार पावर संकट से जूझ रहें हैं। उद्योगों व रिहायशी क्षेत्रों में घंटों-घंटों बिजली गुल रहती है। यह सब तो तब है जब आईपीडीएस (इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) पर बीते पांच साल में 100 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

इस सिस्टम के तहत नये सब स्टेशन व नये ट्रांसफार्मर आदि लगाने का दावा किया गया था। कहा गया था कि यह सब करने के बाद पावर सप्लाई में कोई व्यवधान नहीं आयेगा। लेकिन इस सबके

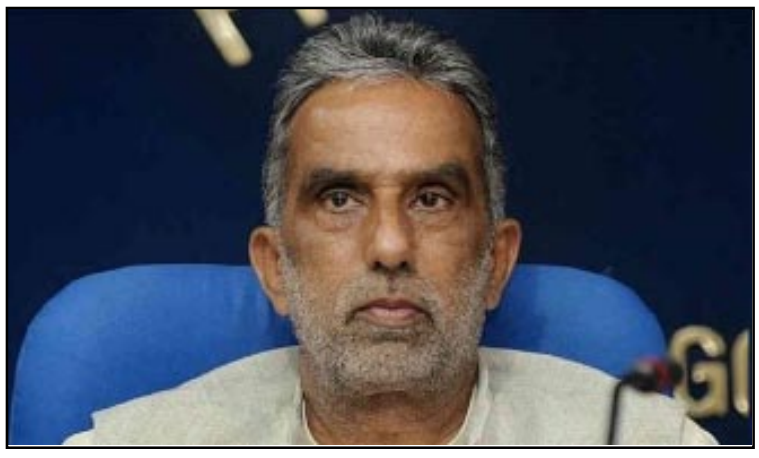

बावजूद लम्बे-लम्बे पावर कट तथा स्थानीय व्यवधान जनता को बराबर परेशान किये हुए है। जनता पूछती है कि वे 100 करोड़ रुपये कौन डकार गया?